## विचार बिन्दु

**प्रतिभा का अर्थ है बुद्धि में नई कोपलें फूटते रहना। नई कल्पना, नया उत्साह, नई खोज और नई स्फूर्ति प्रतिभा के लक्षण हैं। –विनोबा**

# साहित्य, कला और संस्कृति अकादमियों में सन्नाटा पसरा है

राजस्थान में भजन लाल शर्मा सरकार के गठन के 19 माह बाद भी प्रदेश की साहित्य कला, भाषा और संस्कृति के उन्नयन के लिए गठित एक दर्ज़न से अधिक अकादमियों में सन्नाटा पसरा है। अकादमियों में व्याप्त इस सन्नाटे को अगर जल्द नहीं तोड़ा गया तो इसका असर बहुत गहरा होगा। गहलोत सरकार के दौरान गठित अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी अपना इस्तीफ़ा दे चुके है मगर भजन लाल सरकार एक लम्बे अर्से बाद भी अब तक इन अकादमियों को पुनर्गठित नहीं कर पायी है जिससे सम्बंधित सभी प्रकार की गतिविधियां ठप्प पड़ी है। कला,संस्कृति और साहित्य के बिना जीवन अधूरा है। इसीलिए किसी भी देश, प्रदेश, सरकार और समाज को वहां की संस्कृति, कला साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समुचित प्रयास करने होंगे।

राज्य सरकार की अकादमियों के प्रति इस बेरुखी से प्रदेश भर के साहित्य और संस्कृति कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। एक जानकारी के मुताबिक राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ,राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी एवं राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, बाल साहित्य अकादमी, पंजाबी अकादमी, आदि प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले है। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्तियां नहीं होने से प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे चल रही अकादमियां कलाकारों और विद्वानों के लिए पुरस्कार समारोह के आयोजन, ग्रंथों के प्रकाशन के साथ ही नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रही हैं।

पिछली गहलोत सरकार के दौरान भी कई वर्षों तक अकादमियों में नियुक्तियां नहीं हुई थी। इन स्वायत्तशाषी संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य, क्षेत्रीय भाषाओं और लोक साहित्य का संरक्षण, कलाकारों, लेखकों और साहित्यकारों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, नाट्यय महोत्सवों का आयोजन, पारंपरिक लोककलाओं को आधुनिक मंच देना, युवा पीढ़ी में रुचि और चेतना पैदा करना हैं। राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण कलाकारों, शोधार्थियों और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कला, साहित्य, भाषा, संगीत और संस्कृति से जुड़ी अकादमियों के कार्य प्रभावति हो रहे हैं। इन संस्थाओं के लेखकों और कला प्रेमियों के जुड़े होने से नरिाशा का सामना करना पड़ रहा है।

**राजस्थान अपनी आन, बान,शान, शौर्य, साहस, कुर्बानी, त्याग, बलिदान तथा वीरता के लिए सम्पूर्ण विश्व में ख्यात है। राजस्थान को भारतीय संस्कृति का गौरव कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ की स्थापत्य कला, संगीत, नृत्य, लोकगीत, वेशभूषा, हस्तशिल्प, वीर-प्रथाएँ, लोक कथाएँ और बोलियाँ - ये सभी भारत की विविधता में एकता का भव्य उदाहरण हैं। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं से पूरी दुनिया प्रभावित है। राजस्थान साहित्य और संस्कृति के साथ त्योहारों और मेलों के लिए विश्व विख्यात है जो आमजन को कोई न कोई सन्देश देते है। इस सांस्कृतिक सम्पदा को संरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य अकादमियों, संस्कृति विभागों और साहित्य संस्थानों का होता है। लेकिन जब वही संस्थान निष्क्रिय हो जाएँ या खाली पड़े हों, तो यह सम्पदा दम तोड़ने लगती है।**

राजस्थान अपनी आन, बान,शान, शौर्य, साहस, कुर्बानी, त्याग, बलिदान तथा वीरता के लिए सम्पूर्ण विश्व में ख्यात है। कला, साहित्य और सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि विश्व में अपनी अलग पहचान रखती है। राजस्थान को भारतीय संस्कृति का गौरव कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ की स्थापत्य कला, संगीत, नृत्य, लोकगीत, वेशभूषा, हस्तशिल्प, वीर-प्रथाएँ, लोक कथाएँ और बोलियाँ – ये सभी भारत की विविधता में एकता का भव्य उदाहरण हैं। यहाँ ढोला-मारू की प्रेमगाथा है, तेजाजी महाराज की लोक आस्था है, मांड और पिंगल जैसी काव्य विधाएँ हैं। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी आदि क्षेत्रों की अपनी-अपनी सांस्कृतिक पहचान है। राजस्थान की कला और संस्कृति विश्वभर में प्रसिद्ध है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं से पूरी दुनिया प्रभावित है। राजस्थान साहित्य और संस्कृति के साथ त्योहारों और मेलों के लिए विश्व विख्यात है जो आमजन को कोई न कोई सन्देश देते है। इस सांस्कृतिक सम्पदा को संरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य अकादमियों, संस्कृति विभागों और साहित्य संस्थानों का होता है। लेकिन जब वही संस्थान निष्क्रिय हो जाएँ या खाली पड़े हों, तो यह सम्पदा दम तोड़ने लगती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि अकादमियों में बिना भेदभाव के योग्य साहित्यकार, लेखक, संस्कृतकर्मी और कलाकारों की नियुक्ति की जाये ताकि नए प्रतिभाशाली लोगों को उनका समुचित सम्मान और प्रत्साहन मिले।

**–अतिथि सम्पादक,**
**बाल मुकुन्द ओझा,**
**( वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार )**

# सुशासन में जनप्रतिनिधि की आवाज का प्रभावशाली माध्यम: संसदीय समितियाँ

**डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा**

संसदीय समितियां सदन का लघु रूप होती है। लोकतांत्रिक पद्धति में जितनी सदन की कार्यवाही महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार संसदीय समितियों की कार्यवाही भी महत्व रखती है। संसदीय समितियों की कार्यवाही लोकतंत्र की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। देश की विभिन्न राज्यों की विधान सभा की समितियों द्वारा परंपराओं के अनुसार, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, प्रशासन की जवाबदेही और लोकतंत्र की गुणवत्ता का वास्तविक परीक्षण किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने देश के विधान मण्डलों की समितियों की सुदृढता की समीक्षा के लिए सात विधान सभा अध्यक्षों की एक समिति का गठन किया है। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी इस समिति के सदस्य है। यह समिति देश के विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में गठित समितियों का तुलनात्मक अध्ययन कर विधान सभा समितियों की सुदृढता के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस समिति में राजस्थान विधान सभा के साथ मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और ओडिसा विधान सभा के अध्यक्ष भी शामिल है। समिति द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

समितियों की सुदृढता के लिये महत्वपूर्ण सुझाव समिति की पहली बैठक मध्य प्रदेश विधान सभा में आयोजित हुई। इस बैठक में राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ाये जाने के लिये सदस्यों का वर्चुअली जुडाव और समितियाँ में सदस्यों का चयन दलीय आधार के साथ-साथ योग्यता और विशिष्टता के आधार पर भी किया जाना चाहिए। समितियों में चार-पाँच वर्ष पुराने मामलों का परीक्षण होता है। समितियाँ द्वारा निकटस्थ वर्षों के मामलों का परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि समितियों के सुझावों की क्रियान्विति के लिये उसी वर्ष के बजट में समावेश के अवसर मिल सकें। समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति को बढ़ायें जाने के लिये सदस्यों के वर्चुअली/ऑनलाइन जुडने पर विचार किये जाने का सुझाव भी आया।

समितियों की रिपोर्ट पर सदन में हो चर्चा - बैठक में प्रस्ताव आया कि समितियों की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा कराये जाने पर विचार करना चाहिये। इससे विधायकों की समितियों के कार्यों में रुचि बढेगी। सदन में समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा होने से जवाबदेही भी तय होगी। सदन में समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा से विधायकों की समितियों के कार्यों में सहभागिता में वृद्धि हो सकेगी।

राजस्थान विधान सभा में समिति प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, नवाचार व सुधार की दिशा में राजस्थान विधान सभा अग्रणी- राजस्थान विधान सभा में वर्तमान में 17 समितियों कार्यरत हैं। कुछ समितियों जिनका कार्य अपेक्षाकृत सीमित था। उन्हें अन्य अधिक सक्रिय समितियों में सृजनात्मक रूप से विलय कर पुनर्गठित किया गया है जैसे पुस्तकालय समिति को सरकारी आश्वासन समिति में और सदाचार समिति को याचिका समिति में समाहित किया गया है, जिससे समितियों का समेकित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।

राजस्थान विधान सभा में नवाचार- सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति का गठन- सभी समितियों की गतिविधियों की समयबद्ध समीक्षा हेतु सामान्य प्रयोजन समिति का गठन किया गया है। राजस्थान विधान सभा में ऐसी समिति का गठन पहली बार हुआ है। इस समिति की अध्यक्षता स्वयं अध्यक्ष करते हैं और जिसमें सभी समितियों के सभापति शामिल होते हैं

प्रत्येक तीन माह में बैठक आयोजित होती है, जिसमें समितियों की बैठक संख्या, परीक्षणों की प्रगति, सदस्यों की उपस्थिति आदि की गहन समीक्षा की जाती है। यह समिति समितियों की सक्रियता को आंकने का एक पारदर्शी माध्यम बन गई है, जिससे ना केवल कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है, बल्कि सदस्यों की सहभागिता में भी बढ़ोतरी हुई है। अब समिति सदस्यों की वार्षिक उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्युक्ति का निर्णय लिया जाता है। जो सदस्य अत्यंत न्यूनतम उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उन्हें दोबारा समिति में शामिल न करने पर भी विचार किया जाता है।

सुशासन में जनप्रतिनिधि की आवाज का प्रभावशाली माध्यम- संसदीय समितियों के माध्यम से ही जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को सुशासन की व्यवस्था में प्रभावशाली रूप से स्थापित किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि न केवल समितियाँ सक्रिय रहें, बल्कि उनका दायित्व और परिणाम भी जनता तक पहुंचे। यह लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है और दायित्व भी।

अगली बैठक राजस्थान में- समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की अगली बैठक को राजस्थान में किये जाने का प्रस्ताव राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रखा। देवनानी के इस प्रस्ताव को बैठक में चर्चा के बाद स्वीकार किया गया।

**–डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा,**
**उप निदेशक, जनसम्पर्क,**
**राजस्थान विधान सभा**

# सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर टीबी मुक्त राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ते कदम

**जयपुर।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। प्रदेश में 25 जून, 2025 से चल रहे सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान के माध्यम से अब तक 74 लाख (44 प्रतिशत) से अधिक अति संवेदनशील जनसंख्या की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अभियान का लक्ष्य 1.67 करोड़ संवेदनशील व्यक्तियों तक पहुंचना है। स्क्रीनिंग में अब तक 2,35,054 व्यक्तियों में टीबी के लक्षण पाए गए हैं, जिन्हें पुष्टि हेतु स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रभावी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। स्क्रीनिंग का अभियान 21 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य टीबी के छिपे मामलों की शीघ्र पहचान कर समय पर नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पीएलएचआईवी, डायबिटीज रोगी, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, कुपोषित व्यक्ति, धूम्रपान/मद्यपान करने वाले, प्रवासी श्रमिक, आदिवासी समुदाय, पूर्व टीबी रोगी तथा खनन एवं निर्माण स्थलों, जेलों एवं शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है।

अति संवेदनशील जनसंख्या की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अभियान की प्रगति की दैनिक समीक्षा भी की जा रही है। राजस्थान में घर-घर जाकर क्षय रोग के लक्षणों की जांच का यह अभियान, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है। जिला टीमों की मेहनत और आमजन की भागीदारी से समय पर अधिकतम रोगियों की पहचान संभव हो रही है, जिससे संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री के सतत पर्यवेक्षण के चलते प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत वर्ष 2024 में 3,350 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, जिससे समुदाय स्तर पर जागरूकता और भागीदारी में वृद्धि हुई है। इस अभियान में राजस्थान देशभर में तीसरे स्थान पर रहा है। अभियान के तहत अब तक 35,117 निक्षय मित्र पंजीकृत हो चुके हैं, जो टीबी मरीजों को पोषण, मानसिक सहयोग और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। निक्षय पोर्टल के माध्यम से टीबी मरीजों की पहचान, उपचार, एवं भुगतान की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। टेक्नोलॉजी के साथ टीबी उन्मूलन की ओर सटीक और तेज कदम बढ़ाते हुए राज्य में टीबी रोगी खोज अभियान का सर्वेक्षण आशा डिजिटल हेल्थ ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, और इसकी रीयल टाइम निगरानी डैशबोर्ड के जरिए सुनिश्चित की जा रही है। सभी संभावित मामलों में नाट आधारित परीक्षण को प्राथमिकता देकर राज्य ने सटीक व शीघ्र निदान की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। सहभागिता आधारित मॉडल के तहत एनजीओ, सीएसआर भागीदारों और निजी चिकित्सकों की सहभागिता से टीबी नियंत्रण प्रयासों को मजबूती मिली है। जिला स्तर पर इंटर-डिपार्टमेंटल समन्वय के माध्यम से पुलिस, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, श्रम विभाग जैसे विभागों के साथ मिलकर सुगठित व समग्र रणनीति बनाई जा रही है। संवेदनशील समूहों पर केंद्रित, माइक्रो प्लानिंग, 100 प्रतिशत डेटा प्रविष्टि और रिपोर्टिंग के साथ अभियान का संचालन हो रहा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशानुसार जिला और ब्लॉक स्तर पर नाट मशीन (629) माइक्रोस्कोपी, एक्स-रे मशीन, लैब तकनीशियन आदि की क्षमता वृद्धि के प्रयास किए गए हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा वर्ष 2024 में राज्य में कुल 1,71,415 टीबी रोगियों का नोटिफिकेशन किया गया, जो निर्धारित लक्ष्य का 101 प्रतिशत है। जून 2025 तक 89,132 टीबी रोगियों का नोटिफिकेशन किया गया है, जो लक्ष्य का 110 प्रतिशत है। गौरतलब है कि नाट तकनीक टीबी की जल्दी और सटीक पहचान करने में सक्षम है, जिससे रोगी को समय पर उपचार मिल पाता है और संक्रमण का प्रसार भी रोका जा सकता है।

**–तरूण जैन**
**अपनिदेशक सूचना एवं**
**जन सम्पर्क विभाग**

# दलहन आयात नीति- किसानों के लिए घातक - दलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा - 'थोथा चना बाजे घना'

**राजपाल जाट**

नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में दलहन उत्पादन 246.5 लाख टन तथा मांग 267.2 लाख मीट्रिक टन थी, अर्थात मांग की तुलना में उत्पादन 23.7 लाख टन कम था। इसकी पूर्ति के लिए सरकार आयात के विकल्प को अधिक महत्व देती है। अनुमानत: वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2028-29 तक दलहन की मांग में 7.3 लाख मैट्रिक टन की बढ़ोतरी रहेगी। इसके अनुसार वर्ष 2025 में मांग 290 लाख टन होगी तथा उत्पादन 257.38 लाख टन रहेगा अर्थात देश में दलहन की 37.62 लाख टन की कमी रहेगी। वर्ष 2028-29 में दलहन का उत्पादन 318.3 लाख टन तथा मांग 297.9 लाख टन रहेगी। इसके अनुसार देश में दलहन की 20.4 लाख टन कमी रहेगी। इसके उपरांत भी भारत सरकार ने 72.6 लाख मीट्रिक टन का आयात किया है। इस आयातित दलहन को उत्पादन में जोड़ने पर देश के भंडार में 325 लाख टन दलहन है, जबकि मांग 290 लाख मीट्रिक टन की है। मांग से 35 लाख टन दालों का भंडारण अधिक होने से दालों के दाम घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम हो गए। इससे दलहन उत्पादक किसानों को बाजार में अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों में बेचनी पड़ रही है। भारत सरकार ने संसद में किसी भी किसान को घोषित 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' से कम दामों में अपनी उपज बेचने के लिए विवश नहीं होने देने का वचन दिया हुआ है। दूसरी ओर भारत सरकार ने 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' को 'गारंटीड मूल्य' की श्रेणी में रखा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों पर 'मैं धारक को पञ्च सौ रुपये अदा करने का वचन देता हूं' अंकित रहता है, यह भारतीय रिजर्व बैंक की गारंटी है। इसी के कारण कागज के टुकड़े की बाजार में 500 रुपए क्रय शक्ति है, इसका पालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटीड मूल्य तो घोषित किया हुआ है किंतु उसके लिए दंड का विधान नहीं है। इसलिए गारंटी होते हुए भी उत्पादक किसानों को अपना उत्पाद औने-पौने दामों पर बेचना पड़ता है।

विश्व में भारत दालों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत सरकार ने दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता का संकल्प व्यक्त किया हुआ है। वर्ष 2021-22 में खरीफ एवं रबी में मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, चना सभी दलहनों का उत्पादन 27.3 मिलियन टन था, जो वर्ष 2022-23 में 26.1, वर्ष 2023-24 में 24.3 तथा वर्ष 2024-25 के द्वितीय अग्रिम आकलन के अनुसार 23.0 मिलियन टन रह गया। इसमें चना वर्ष 2021-22 में 13.4, वर्ष 2022-23 में 12.3, वर्ष 2023-24 में 11.0 मिलियन टन रह गया। चने के आयात पर 65% तक आयात शुल्क लगाया गया था, जिसे घटाकर शून्य कर दिया गया।

पीली दाल का उपयोग चना एवं अरहर के विकल्प के रूप में किया जाता है तथा बेसन जैसे उप उत्पाद तैयार किए जाते है। पीली दाल चना एवं अरहर की तुलना में कम मूल्य पर प्राप्त होती है। दिसंबर 2023 में पीली दाल को आयात शुल्क से मुक्त करने से दलहन के आयात में पीली दाल की भागीदारी 2023-24 में 24.6% से बढ़कर 2024-25 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक 37.4 प्रतिशत हो गई। इससे देश में दलहनों का उत्पादन विपरीत रूप से प्रभावित होता है। किसानों को तो घोषित 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' भी प्राप्त नहीं हो पाता है। उन्हें औने पौने दामों में अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' ने वर्ष 2025-26 की 'खरीफ फसलों की मूल्य नीति' में पीली दाल के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की है।

इसके उपरांत भी भारत सरकार ने 31 मई 2025 को अधिसूचना प्रसारित कर पीली दाल के आयात की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। यह 'करेला और नीम चढ़ा' की लोकोक्ति को चरितार्थ करता है। अलनीनो के प्रभाव के कारण वर्ष 2016 एवं 2017 में उत्पादन की मात्रा घट गई थी, जिसका कारण सरकार ने अलनीनो के प्रभावको माना था। देश में उस समय आयातित चार मिलियन टन पीली दाल के ढेर लग गए। उसे पटरी पर लाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई एवं सरकारी खरीद को प्रोत्साहित कर वर्ष 2018 में उत्पादन के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी की नीति अपनाई गई। जिससे स्थिति में सुधार संभव हुआ।

भारत सरकार की दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की घोषणा:-

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार दलहन फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2021-22 में 307.71 लाख हेक्टर था। जो वर्ष 2024-25 में घटकर 278.5 लाख हेक्टर रह गया। परिणामस्वरूप उत्पादन वर्ष 2021-22 के 273.02 लाख मीट्रिक टन से घटकर 2024-25 में 252.38 लाख टन रह गया। दालों का आयात खर्च वर्ष 2021-22 से 2024-25 में 15,540 करोड रुपए से बढ़कर 46,428 करोड रुपए हो गया। इसी प्रकार आयात की मात्रा भी वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 2,51,965 मीट्रिक टन से बढ़कर 72,55,585 मीट्रिक टन हो गया।

कानपुर स्थित 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ पल्सेस रिसर्च' के निदेशक जी. पी. दीक्षित के अध्ययन के अनुसार चना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहने वाले मध्य प्रदेश का चना उत्पादन का क्षेत्रफल 5 वर्ष की अवधि में 35 लाख हेक्टर से घटकर 20 लाख हेक्टर रह गया। सिंचित क्षेत्र बढ़ाने तथा तुलनात्मक रूप से गेहूं के दाम चने की अपेक्षा अधिक मिलने से चने का स्थान गेहूं की खेती ने ले लिया। दलहन खेती मौसम की संवेदनशीलता से अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होती है।

आत्मनिर्भरता के लिए दलहन खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसानों को 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' प्राप्ति सुनिश्चित करना अपरिहार्य है।

अरहर, उड़द, मसूर की भांति चना एवं मूंग की दाने दाने की खरीद का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' के प्रावधानों में समुचित संशोधन कर कुल उत्पादन में से 25% से अधिक खरीद नहीं करने के प्रतिबंध को हटाने, खरीद की अवधि अधिकतम 90 दिन को विलुप्त कर वर्ष भर खरीद चालू रखने तथा मार्गदर्शिका के अनुसार तीन दिन में भुगतान करने की पालना कठोरता से करना समीचीन है। गेहूं एवं धान खरीद नीति की भांति दलहन के दाने-दाने की खरीद करना आवश्यक है। उसी क्रम में न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार भावों के संधारण के लिए आयात शुल्क का निर्धारण करना चाहिए, जिसमें आयात शुल्क 100% से कम नहीं हो।

भारत सरकार की ओर से वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 वर्षों में भारत को अरहर, उड़द, मसूर, चना की दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की नीति तैयार करने का वचन दिया हुआ है। इस दिशा में दलहन उपज के बाजार भाव में न्यूनतम समर्थन मूल्य से गिरावट नहीं आवे, जिससे किसानों को उनके उत्पादों के घोषित न्यूनतम दाम प्राप्त हो सके। किसानों को लागत मूल्य से वंचित नहीं रहना पड़े। यदि किसानों को लागत मूल्य प्राप्त नहीं होता है तो उत्पादन में उनका उत्साह ठंडा हो जाता है। घरेलू बाजार तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का अंतर अधिक होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद विपरीत रूप से प्रभावित होती है। इस समय उड़द, चना, मसूर, मूंग की उपज की स्थिति चिंताजनक है। यदि यही स्थिति जारी रहती है तो सस्ते आयात के कारण भारत का घरेलू दाल व्यापार समाप्त होकर भारत आत्मनिर्भर होने के स्थान पर शत-प्रतिशत आयात पर निर्भर हो जायेगा। इससे मुक्ति दिलाने के लिए आयात-निर्यात नीति की समीक्षा कर उसे उत्पादक किसानों के अनुकूल बनाना महत्वपूर्ण कदम रहेगा।

यह आश्चर्य मिश्रित दुखद तथ्य कि दलहन उत्पादन में भारत की वैश्विक भागीदारी 28.02% है तब भी भारत उन देशों से आयात करता है जिनमें से किसी भी देश की वैश्विक भागीदारी 5.4% से अधिक नहीं है। वर्ष 2017 से 2025 तक की अवधि में आयात-निर्यात नीति में अस्थिरता रही तथा उपभोक्ताओं को कम वहनीय मूल्य पर दालों की उपलब्धता के लिए, उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य तथा आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्यों के प्रतिकूल, नीतियां बनाई गई।

**–रामपाल जाट,**
**राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान**
**महापंचायत**

## राशिफल गुरूवार 17 जुलाई, 2025

**पंडित अनिल शर्मा**

सावन मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, रेवती नक्षत्र रात्रि 3:39 तक, अतिगंड योग प्रात: 9:24 तक, विष्टि करण प्रात: 8:06 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:39 से मीन राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-कर्क चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। भद्रा आज प्रात: 8:06 तक है। आज कालाष्मी, शीतला सप्तमी (उड़ीसा) है। पंचक रात्रि 3:39 तक है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** शुभ सूर्योदय से 7:29 तक, चर 10:52 से 12:33 तक, लाभ-अमृत 12:33 से 3:55 तक, शुभ 5:37 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:47, सूर्यास्त 7:18

### मेष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

### सिंह

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में आज प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा।

### धनु

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। घर-परिवार में अतिथियों उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

### वृष

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

### कन्या

स्वस्थ्य में सुधार होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

### मकर

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिलेगा। आज महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

### मिथुन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

### तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना बनेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

### कुंभ

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

### कर्क

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी बनी रहेगी।

### वृश्चिक

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

### मीन

आज अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।